

मध्यप्रदेश की सत्ता की चाबी है आदिवासी वोटरों के पास

■ भाजपा और कांग्रेस, दोनों तरफ से इन्हें साधने की हो रही भरपूर कोशिश

■ 84 सीटों पर है निर्णायक संख्या, 47 सीटों हैं जनजातियों के लिए आरक्षित

साल के अंत में विधानसभा चुनाव के मैदान में उत्तरनेवाले मध्यप्रदेश में सियासी समीकरण साधने का जलन तेज हो गया है। सत्ता में बदलाव रहने का भाजपा का लक्ष्य हो या सत्ता में वापसी की कांग्रेस की कोशिशें, दोनों के लिए उम्मीदों का सूजन आदिवासी वोटरों से ही उदित होना है। यानी आदिवासी वोट बैंक जिसके साथ चल देगा, सत्ता के दरवाजे उसी के लिए खुलेंगे। इसका असर इन दिनों राज्य की राजनीति और चुनावी तैयारियों पर भी भरपूर देखा जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस, दोनों आदिवासी समुदाय को अपने साथ जोड़ने की जबरदस्त कवायद कर रहे हैं। राज्य में आदिवासी वर्ग की भूमिका

सरकार बनाने और बिंगाड़ने में महत्वपूर्ण रही है। यही कारण है कि 2003 के 15 वर्ष बाद जब आदिवासी वोट ने करवट ली, तो 2018 में भाजपा की सरकार चली गयी। उस साल भाजपा की सीटें 32 (एक निर्दलीय) से घटकर आधी यानी 16 बचीं। कांग्रेस के पास 2013 में 15 आदिवासी सीटें थीं, जो 2018 में बढ़कर 30 हो गयीं। राज्य में वैसे तो 47 सीटें आदिवासियों आपनी ओर खींचने में लगी हुई हैं। भाजपा की तरफ से आदिवासियों को साधने के लिए पहले प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी और पिंड जेंडा के अलावा अमित शाह राज्य का दौरा कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस के

संपादकीय

कितना गंभीर है प्रस्ताव

पा किसान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वह भारत के साथ सभी गंभीर मसलों पर बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि युद्ध कोई विकल्प नहीं रह गया है। उनकी इस बात में असहमति को कोई गुजारण नहीं किया जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ कोई पहली बार बातचीत की पेशकश नहीं कर रहे हैं। इसी साल जनवरी में भी उन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया था। अगर उस प्रस्ताव के बाद हालात में कोई बदलाव नहीं आया, तो उसकी भी ठोस वजहें मौजूद हैं। ध्यान रखे, पिछले बारों में भारत की तरफ से द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती देने की कम कोशिश नहीं हुई। साल 2014 में सत्ता में आने के साथ ही प्रधानमंत्री ने दोष प्रवास शुरू कर दिये थे। उन प्रवासों का फल भी दिख रहा था। बात बिंबड़ी शुरू हुई तब, जो भारत की लाख कोशिशों के बावजूद सीमा पर से आतंकी गतिविधियों पर लगाने की कोई सार्थक कोशिश नहीं दिखी। मजबूरन भारत को इस आतंकी हमलों पर रोक लगाने की पहल खुद करनी पड़ी। इसके साथ ही भारत ने वह भी स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। दोनों देशों के रिश्तों में दूसरा बड़ा फैक्टर कश्मीर का सावल है।

पाकिस्तान अंदरूनी राजनीतिक संकट से भी गुजर रहा है, जहां हटाए गए प्रधानमंत्री इमरान खान और आमीन के बीच टकराव बना हुआ है। दूसरी ओर, इमरान जनता के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं।

मसला है। वह मैके-वेमैके इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहता है। ऐसे में वह कैसे माना जा सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सच्चाय रिश्तों को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं? अगर वह संरेश दें कि पाकिस्तान में कहरांथी और आतंकी तत्वों को फूलने-फूलने नहीं दिया जायेगा तो असंभव नहीं कि दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो जाये, लेकिन इन संघाताओं के बीच सच्चाई को नहीं भूला जा सकता कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकरें भी आमीन के बावजूद एक अपराधी हैं और, शहबाज सरकार तो चुनी हुई भी नहीं है। इधर पाकिस्तान अंदरूनी राजनीतिक संकट से भी गुजर रहा है, जहां हटाए गये प्रधानमंत्री इमरान खान और आमीन के बीच टकराव बना हुआ है। दूसरी ओर, इमरान जनता के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं। पाकिस्तान में आने वाले समय में संसदीय चुनाव भी प्रस्तावित हैं। इसके बाद वह स्पष्ट होगा कि इमरान या उनके विरोधियों में से जनता किसके साथ है। असल में, दोनों देशों के बीच कोई सार्थक बातचीत तभी हो सकती है, जब पाकिस्तान में सत्ता के अलग-अलग केंद्रों की इस पर एक रथ हो। साथ ही, उसे सीमापार से आतंकवाद का खेल भी बंद करना होगा।

कोयले का निष्कर्षण एक महत्वपूर्ण उप-उत्पाद के साथ होता है, जिसे ओवरबर्डन के नाम से जाना जाता है। कोयले के खुले खनन के दौरान, कोयले की परत के ऊपर स्थित परत को ओवरबर्डन के रूप में जाना जाता है, जिसने प्रचुर मात्रा में सिलिका सामग्री के साथ निट्री, जलोढ़ देते और बलुआ पातर शामिल होते हैं। नीचे से कोयला निकालने के लिए ओवरबर्डन को हटा दिया जाता है। बाद में, कोयला निष्कर्षण पूरा होने पर, नीटि को उसका गूल आकार प्रदान करने के लिए ओवरबर्डन का उपयोग बैकफिलिंग के लिए किया जाता है।

राजीव आर मिश्रा

भले ही अपने उपभोक्ताओं के लिए कोयला/ लिमाइट का उत्पादन और वितरण करने का ही सामान्य हो, पिछरे भी कोयला मंत्रालय के मार्गशिर्ण में कोयला और लिमाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने लोक से हट कर ओवरबर्डन से बहुत कम कीमत पर रेत का उत्पादन करने वाली एक अनोखी पहल की है। इस पहल से न केवल ओवरबर्डन के कारण रेत गांव से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिल रही है, बल्कि निर्माण के लिए सस्ती रेत प्राप्त करने का विकल्प भी मिल रहा है। पाकिस्तान भारत के अपने क्षेत्र में किये गये अनुच्छेद 370 से जुड़े बदलावों को तो मुझ बनाता है, हालांकि वह पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन यह नहीं देखता कि विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में रेत का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और अगले पांच वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सोआइएल), नैकेली लिमाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगेरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में रेत के उत्पादन को अवधिकरण करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा चुका है।

कोयले का खुले खनन के दौरान, कोयले की परत के ऊपर स्थित

परत को ओवरबर्डन के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रस्तुर मात्रा में सिलिका सामग्री के साथ मिट्टी, जलोढ़ रेत और बलुआ पथर शामिल होते हैं। नीचे से कोयला निकालने के लिए ओवरबर्डन को हटा दिया जाता है। बाद में, कोयला निष्कर्षण पूरा होने पर, भूमि को उसका सूल आकार प्रदान करने के लिए औवरबर्डन का उपयोग बैकफिलिंग के लिए ओवरबर्डन का उपयोग की ओर दिया जाता है। इसके बाद यह तरह के रूप से अपराधिक उपकरण का विकल्प होता है।

इस ओवरबर्डन का परंपरागत रूप से



अगले कुछ वर्षों में, प्रैद्योगिकी की प्रगति और हमारे देश में विभिन्न स्थानों में भारी मात्रा में होने वाले रेत का उत्पादन के साथ, रेत के प्रति धन मीटर कीमत में काफी कमी आएगी, जिससे आगे आदमी को निर्माण उद्देश्य के लिए सस्ती रेत उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इस ओवरबर्डन का निष्कर्षण एक महत्वपूर्ण उप-उत्पाद के साथ होता है, जिसे ओवरबर्डन के नाम से जाना जाता है। हालांकि, सतत अभ्यास और सकलूल इकोनॉमी पर बढ़ते फोकस के साथ, ओवरबर्डन के लिए वैकल्पिक उपयोग की खोज करने और इसे करने से कंचन में बदलने की दिशा में बदलाव आया है।

प्रथम पहल: इस तरह के रूपांतरण की पहली व्यावसायिक पहल सीआइएल की सहायता कीमत का लगभग 10 प्रतिशत थी। यह रेत प्रधानमंत्री आवास सोनाजा (पीएमएवड) के तहत कम लागत वाले घर बनाने के लिए नागपुर इम्पूवर्मेंट ट्रस्ट को दी गयी थी। इसके अलावा दो और विभागीय पहल भी शुरू की गयी।

पायलट परियोजनाओं की सफलता पर, डब्ल्यूसीएल ने नागपुर के पास गोडांगांव खदान में देश के सबसे बड़े रेत उत्पादन करने के लिए नागपुर इम्पूवर्मेंट ट्रस्ट को नेतृत्व रेत मिल रही है।

कलेक्टर से कंचन: एक आदर्श बदलाव: ओवरबर्डन, जिसे कभी अपशिष्ट या बेकर पदार्थ समझा जाता था, अब उसे एक मूल्यवान संसाधन माना जा रहा है। रेत प्रस्तुरण इकाइयों भी जबरदस्त रेत के लिए काम करने के लिए कोयला मंत्रालय के अधिकारी द्वारा लाइसेन्स दी गयी।

कोयला कीमत लगभग 160 प्रति धन मीटर थी, जो बाजार की माध्यम से बेचा जा रहा है, जिससे सामाजिक कल्याण में योगदान दे रहा है।

कोयले कीमत लगभग 160 प्रति धन मीटर थी, जो बाजार की माध्यम से बेचा जा रहा है।

याया गया। इसकी कीमत लगभग 160 प्रति धन मीटर थी, जो बाजार की माध्यम से बेचा जा रहा है।

अन्य छोटी इकाइयों को दिया जा रहा है।

बाकी रेत को बाजार में खुली नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिससे सामाजिक कल्याण में योगदान दे रहा है।

कोयला कीमत लगभग 160 प्रति धन मीटर थी, जो बाजार की माध्यम से बेचा जा रहा है।

याया गया। इसकी कीमत लगभग 160 प्रति धन मीटर थी, जो बाजार की माध्यम से बेचा जा रहा है।

अन्य छोटी इकाइयों को दिया जा रहा है।

बाकी रेत को बाजार में खुली नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिससे सामाजिक कल्याण में योगदान दे रहा है।

याया गया। इसकी कीमत लगभग 160 प्रति धन मीटर थी, जो बाजार की माध्यम से बेचा जा रहा है।

अन्य छोटी इकाइयों को दिया जा रहा है।

बाकी रेत को बाजार में खुली नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिससे सामाजिक कल्याण में योगदान दे रहा है।

याया गया। इसकी कीमत लगभग 160 प्रति धन मीटर थी, जो बाजार की माध्यम से बेचा जा रहा है।

अन्य छोटी इकाइयों को दिया जा रहा है।

बाकी रेत को बाजार में खुली नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिससे सामाजिक कल्याण में योगदान दे रहा है।

याया गया। इसकी कीमत लगभग 160 प्रति धन मीटर थी, जो बाजार की माध्यम से बेचा जा रहा है।

अन्य छोटी इकाइयों को दिया जा रहा है।

बाकी रेत को बाजार में खुली नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिससे सामाजिक कल्याण में योगदान दे रहा है।

याया गया। इसकी कीमत लगभग 160 प्रति धन मीटर थी, जो बाजार की माध्यम से बेचा जा रहा है।

अन्य छोटी इकाइयों को दिया जा रहा है।

बाकी रेत को बाजार में खुली नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिससे सामाजिक कल्याण में योगदान दे रहा है।

याया गया। इसकी कीमत लगभग 160 प्रति धन मीट

